

स्तर पर 'लखपति दीदी' के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने अन्य ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि घर से बाहर निकलकर स्वरोजगार अपनाने से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में नई पहचान मिलती है। मिशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपने बड़े भाई के रूप में संबोधित करते हुए आभार जताया और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना और बिहान जैसी पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है—जो बहनों की तरफ़ी।

संक्षिप्त समाचार

बाइक को 500 मीटर तक घसीटीटी चली गई तेज रफ्तार कार,दो युवक गंभीर

रायपुर। छुईखदान थाना क्षेत्र के जोरतराई रोड पर रविवार रात तेज रफ्तार का खौफनाक मंजर देखने को मिला. धमधा से लौट रहे बाइक सवार दो युवकों को सामने से आ रही तेज रफ्तार सफेद कार ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक कार में फंस गई और कार उसे करीब 500 मीटर तक घसीटीटी चली गई. हादसे में बाइक सवार हुलास साहू और योगेश साहू, निवासी मदनपुर खैरगढ़, गंभीर रूप से घायल हो गए, जानकारी के मुताबिक दोनों युवक रविवार रात बाइक से धमधा की ओर से वापस लौट रहे थे, इसी दौरान जोरतराई रोड के पास सामने से आ रही सफेद कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद भी कार नहीं रुकी और बाइक कार में फंसकर काफी दूर तक घिसटती चली गई. हादसे के बाद मौके पर अपरा-तपरी मच गई. घायलों को तत्काल धमधा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें भिलाई रेफर कर दिया. बताया जा रहा है कि घायलों में से एक की हालत नाजुक बनी हुई है. इधर घटना की जानकारी मिलते ही घायलों के परिजन छुईखदान थाने पहुंचे और कार चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. परिजनों ने कार चालक पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया है. छुईखदान थाना प्रभारी बिलकिस बानो ने बताया कि घायलों के परिजनों की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और कार चालक की भूमिका क्या रही, इसकी भी पड़ताल की जा रही है.

महतारी वंदन योजना से बेटी के भविष्य को संवार रही भानमती

रायपुर। राज्य शासन की महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी साबित हो रही है। योजना के तहत प्राप्त महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है, जो महिलाओं की छोटी-छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। कोण्डगांव जिले के ग्राम बड़ेकनेरा निवासी भानमती बघेल के लिए भी महतारी वंदन योजना आर्थिक मजबूती और आत्मविश्वास का आधार बनी है। भानमती ने बताया कि योजना के तहत हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि से वह अपनी तीन वर्षीय बेटी देवांशी बघेल के भविष्य के लिए सुरक्षित कर रही हैं। उनका कहना है कि आज की छोटी-सी बचत आने वाले समय में बेटी की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए बड़ा सहारा बनेगी। भानमती ने कहा कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि ने उन्हें अपने परिवार की जरूरतों के साथ-साथ बेटी के भविष्य के लिए नियमित रूप से बचत करने का अवसर दिया है। उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य शासन द्वारा संचालित इस योजना के प्रति आभार व्यक्त किया। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भानमती ने कहा कि विष्णु भैया द्वारा महिलाओं को दी जा रही महतारी वंदन योजना की राशि भाई-बहन के रिस्ते में स्नेह और विश्वास को और मजबूत करने का माध्यम बन रही है। उनके लिए यह सहायता राशि केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि अपनी बेटी के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य के लिए एक मजबूत आधार भी है।

तालाब में पाली मछलियां, मुनाफे से संवारी जिंदगी—शंकर कुड़ियम बने आत्मनिर्भरता की मिसाल

रायपुर। जिले के ग्रामीण अंचलों में शासकीय योजनाएं किसानों और ग्रामीणों के लिए आय के नए अवसर खोल रही हैं। मत्स्य पालन विभाग के मार्गदर्शन एवं योजनाओं का लाभ लेकर जिले के शंकर कुड़ियम ने निजी तालाब में मछली पालन को आय का बेहतर साधन बनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। शंकर कुड़ियम ने 0.45 हेक्टेयर निजी तालाब में मछली पालन का कार्य शुरू किया। मत्स्य पालन विभाग द्वारा तालाब की तैयारी में मार्गदर्शन देने के साथ मत्स्य पालन प्रसार योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत अनुदान पर उन्नत मत्स्य बीज एवं मछली पकड़ने के लिए जाल सामग्री उपलब्ध कराई गई। शासकीय योजना से मिले सहयोग और तकनीकी मार्गदर्शन से उन्हें मछली पालन को व्यवस्थित एवं लाभकारी तरीके से संचालित करने में मदद मिली। शंकर कुड़ियम ने अपने तालाब से 594 किलोग्राम मछली का उत्पादन प्राप्त किया। इस व्यवसाय में उनकी कुल लागत 0.350 लाख (35 हजार) रही, जबकि उन्होंने 1.306 लाख (1 लाख 30 हजार 600 रुपये) की कुल आय अर्जित की। इस तरह उन्हें 0.956 लाख यानी 95,600 का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। यह सफलता बताती है कि यदि स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए वैज्ञानिक पद्धति और शासकीय योजनाओं का लाभ लिया जाए, तो मत्स्य पालन ग्रामीण परिवारों के लिए आय का मजबूत एवं टिकाऊ माध्यम बन सकता है। मत्स्य पालन विभाग के मार्गदर्शन और शासकीय योजना के सहयोग से शंकर कुड़ियम ने मछली पालन को सफल व्यवसाय के रूप में अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है।

‘विष्णु भैया’ ने बहनों को दिया सुरक्षा और सम्मान का भरोसा

■ बहनों के स्नेह से सजी ‘विष्णु भैया’ की कलाई, सुरक्षा–सम्मान का लिया संकल्प

■ बहनों के ‘विष्णु भैया’ बने मुख्यमंत्री श्री साय, राखी के साथ मिला स्नेह और विश्वास

रायपुर/ संवाददाता

रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले राजधानी रायपुर में आज भाई-बहन के स्नेह और राष्ट्ररक्षा के संकल्प का भावपूर्ण संगम देखने को मिला। बलवीर सिंह जुनेजा ईंडोर स्टेडियम में आयोजित ‘स्नेह की डोर’ कार्यक्रम में केंद्रीय सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस के जवानों की कलाइयों पर जब स्कूली बेटियों, दिव्यांग बेटियों और महिला स्व-सहायता समूहों की दीदीयों ने रक्षा सूत्र बांधे तो पूरा वातावरण आत्मीयता, सम्मान और कृतज्ञता के भाव से भर उठा। कार्यक्रम का सबसे

विष्णु के सुशासन में गांव की बेटियां बन रहीं आत्मनिर्भर....

■ बिहान से मिला संबल, विष्णु भैया की योजनाओं ने बढ़ाया आत्मविश्वास

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में लागू हो रहे विष्णु के सुशासन का लाभ गांव-गांव तक पहुंच रहा है। शासन की योजनाओं और ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनने के साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। गैरिला विकासखंड के ग्राम पंचायत चुकतीपानी की श्रीमती बबली यादव ऐसी ही मेहनतकश महिला हैं, जिन्होंने विष्णु भैया की सरकार की योजनाओं से मिले अवसरों को अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से सफलता में बदला है। बबली यादव जागृति महिला स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष हैं। उन्होंने समूह के माध्यम से ऋण

भावुक क्षण तब आया, जब वर्ष 2017 में रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पूर्व नक्सली मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद उपनिरीक्षक श्री युगल किशोर वर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती माधुरी वर्मा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की कलाई पर राखी बांधी। मुख्यमंत्री इस अवसर पर भावुक हो उठे। उन्होंने शहीद श्री वर्मा के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए शहीद जवानों के परिवारों के साथ सदैव खड़े रहने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राखी का यह भागा केवल भाई-बहन के स्नेह का बंधन नहीं, बल्कि एक शहीद परिवार के विश्वास और अपनत्व का प्रतीक है। हमारे वीर जवानों का बलिदान और उनके परिवारों का त्याग छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूल सकता। शहीदों के परिवार हमारे अपने परिवार हैं और उनके सम्मान, स्वाभिमान तथा हर सुख-दुःख में उनके साथ खड़े रहने का यह रिस्ता सदैव अटूट रहेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि देश और छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के आतंक से मुक्त करने के लिए हमारे सुरक्षा बलों ने अदम्य

प्राप्त कर कंप्यूटर खरीदा और अपने घर पर ही फोटो कॉपी एवं कंप्यूटर संबंधी कार्य शुरू किया। गांव में ही यह सुविधा उपलब्ध होने से ग्रामीणों को आवश्यक कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। वहीं बबली को नियमित आय का साधन भी मिल गया। एक छोटे से प्रयास ने उनके आत्मविश्वास को नई उड़ान दी और उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया। बबली यादव ने अपने आय बढ़ाने के लिए खेती-किसानी से जुड़े कार्यों को भी अपनाया। उन्होंने मशरूम उत्पादन शुरू किया, जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी होने लगी। इसके साथ ही वे पीजी समूह के माध्यम से महुआ खरीदी का कार्य भी कर रही हैं। इस पहल से उन्हें आय का एक और साधन मिला है और स्थानीय स्तर पर ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों के अवसर भी बढ़े हैं। बबली यादव बताती हैं कि फोटो कॉपी एवं कंप्यूटर कार्य, मशरूम उत्पादन और महुआ खरीदी जैसे विभिन्न कार्यों से उनकी मासिक आय लगभग 10 हजार रुपये तक हो जाती है।

राजधानी रायपुर में धोखाधड़ी और चोरी के सात मामले दर्ज

■ 36.50 लाख की ठगी से लेकर वाहन चोरी तक

रायपुर/ संवाददाता

राजधानी रायपुर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में धोखाधड़ी, वाहन चोरी, सोने के आभूषण की चोरी और मारपीट के कई मामले सामने आए हैं। पुलिस ने संबंधित मामलों में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनमें शेर बानार में अधिक मुनाफे का झांसा देकर 36 लाख 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी का मामला भी शामिल है। दीनदयाल उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र में अवकाश श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई कि मोबाइल

फोन धारक ने उन्हें शेर बानार में कारोबार के नाम पर अधिक मुनाफा कमाने का झांसा दिया। आरोपी के बताए बैंक खाते में अलग-अलग किस्तों में कुल 36 लाख 50 हजार रुपये जमा कराए गए। रकम वापस नहीं करने पर पीड़ित ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में थाना परिसर के बाहर पार्किंग स्थल से हीरो स्पेंडर मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 04 एमवी 0787 चोरी हो गई। वाहन की कीमत करीब 20 हजार रुपये बताई गई है। सौरभ शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। गोलबाजार थाना क्षेत्र में जवाहर



साहस का परिचय दिया है और अनेक जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। नक्सलवाद के अंत की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ हमारी बहनों के लिए सुरक्षा और विश्वास का सबसे बड़ा उपहार है। अब वह समय आ रहा है जब नक्सल हिंसा के कारण किसी बहन का सुहाग नहीं उजड़ेगा, किसी मां को अपना बेटा नहीं खोना पड़ेगा और

ई-रिक्शा में धक्का-मुक्की के बीच सोने की चेन पार, पुलिस जांच में जुटी

रायपुर। राजधानी रायपुर में महिला अधिकारी के साथ चेन खेचिंग की वारदात सामने आई है. जेल रोड से पेंशनबाड़ा के बीच ई-रिक्शा में महिला अधिकारी के गले से सोने की चेन पार कर दी गई. बताया जा रहा है कि घटना के तीन दिन बाद कोतवाली थाना में रिपोर्ट लिखाई गई है. पीड़िता जनता कॉलोनी गुडियारी निवासी मंजूलता साहू राज्य परिवहन कार्यालय समग्र शिक्षा, रायपुर में सहायक संचालक हैं. जानकारी के मुताबिक, घटना 18 अगस्त की सुबह की है. करीब सुबह 10:15 बजे मंजूलता साहू दोपहिया से पेंशनबाड़ा स्थित बोर्ड ऑफिस जाने के लिए निकली थीं. रास्ते में बारिश तेज होने से ई-रिक्शा में सवार हो गई. ई रिक्शा खालसा स्कूल होते हुए आम्बेडकर चौक पहुंचा।

भाई का स्नेह, बहनों का अधिकार, विष्णु भैया के साथ आत्मनिर्भर परिवार

रायपुर। महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके परिवारों की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के तहत 30वीं किस्त की राशि मिलने से मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के मोहला विकासखंड के ग्राम एकटकन्दार निवासी हितग्राही श्रीमती गनिता बोदले की रक्षाबंधन की खुशियां दोगुनी हो गई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को 'विष्णु भैया' कहते हुए योजना के लिए आभार व्यक्त किया। श्रीमती गनिता बोदले ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत उन्हें हर माह एक हजार रुपए की सहायता राशि नियमित रूप से प्राप्त हो रही है। इस राशि का उपयोग वे घरेलू जरूरतों, परिवार के खर्च और अपनी छोटी बेटी को देखभाल में करती हैं। उन्होंने बताया कि उनके पति द्वाइवर का कार्य करते हैं, ऐसे में महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि परिवार के लिए आर्थिक सहयोग का महत्वपूर्ण माध्यम बनी है। गनिता ने कहा कि रक्षाबंधन से पहले महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त की राशि खाते में आने से उन्हें काफी खुशी हुई है। इस राशि से वे अपने भाइयों के लिए राखी और मिठाई खरीदेंगी। उन्होंने कहा कि त्योहार के समय मिलने वाली यह सहायता परिवार को छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने में काफी मददगार साबित होती है।

कवर्धा की प्रतिभा एक दिन बनेगी देश का गौरव-उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

उप मुख्यमंत्री ने 171 मेधावियों का किया सम्मान प्रतिभा को मिला बड़ा मंच और सपनों को नई उड़ान

■ पहली बार इतने बड़े स्तर पर हुआ आयोजन, वनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को भी मिला सम्मान

रायपुर/ संवाददाता

मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर सफलता हासिल करने वाले कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के 171 मेधावी विद्यार्थियों के लिए यह दिन खास और यादगार रहा। पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम, कवर्धा में आयोजित मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने कक्षा



10वीं एवं 12वीं में 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि के चेक एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। कवर्धा में पहली बार इतने बड़े स्तर पर आयोजित इस समारोह में वनांचल क्षेत्र के विद्यार्थियों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इस पहल ने ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में पढ़ने वाले

बच्चों की प्रतिभा को पहचान और प्रोत्साहन देने का संदेश दिया। समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने विद्यार्थियों से आत्मीयता के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया, उनकी पढ़ाई और रचियों के बारे में जाना तथा उनके सवालों और जिज्ञासाओं पर चर्चा की। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरक पुस्तकें भी भेंट कीं,

किसी बहन को अपने भाई के सकुशल घर लौटने की चिंता नहीं सताएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प तथा सुरक्षा बलों के साहस और पराक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता ने बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में शांति और विकास

बहनों की बेहतरी विष्णु भैया का मान महतारी वंदन योजना की किश्त मिलने से उत्साहित हैं महिलाएं...

■ महतारी वंदन योजना से बबीता ठाकुर के जीवन में आई खुशहाली

रायपुर/ संवाददाता

महतारी वंदन योजना प्रदेश की माताओं बहनों के लिए आर्थिक संबल और आत्मनिर्भरता का माध्यम बन रही है। योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि से महिलाएं अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई और घर परिवार की जरूरत में भी सहयोग कर पा रही हैं। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा

के नए युग का मार्ग प्रशस्त किया है। इस परिवर्तन में बस्तर की जनता का विश्वास और सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बस्तर की पहचान हिंसा से नहीं, बल्कि शांति, विकास, समृद्ध जनजातीय संस्कृति, पर्यटन और नई संभावनाओं से होगी। लंबे समय तक नक्सलवाद के कारण विकास से वंचित रहे क्षेत्रों तक सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और रोजगार के अवसर तेजी से पहुंचाए जा रहे हैं। सरकार का संकल्प बस्तर को देश के श्रेष्ठ और विकासित आदिवासी अंचलों में शामिल करना है। ‘स्नेह की डोर’ कार्यक्रम में सीआईएसएफ् बीएसएफ् आईटीबीपी, सीआरपीएफ् सेना और पुलिस के लगभग 800 जवान शामिल हुए। स्कूली छात्राओं, दिव्यांग बेटियों, स्वच्छता दीदीयों, ड्रोन दीदीयों, लखपति दीदीयों और महिला स्व-सहायता समूहों की बहनों ने जवानों की कलाइयों पर राखी बांधी और राष्ट्र तथा समाज की सुरक्षा में उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा आत्मीय और अद्भुत दृश्य पहली बार देखा है।

बहनों की बेहतरी विष्णु भैया का मान महतारी वंदन योजना की किश्त मिलने से उत्साहित हैं महिलाएं...

बताया कि योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग बच्चों की दैनिक उपयोग की सामग्री खरीदने में भी किया जा रहा है। साथ ही घरेलू कार्य के लिए भी उपयोग कर रही हैं। उन्होंने भावुक होकर कहा कि इस योजना की 31 वीं किस्त की राशि मिलने से उनके परिवार के सदस्य खुश हैं। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के पर्व पर मिली एक हजार रुपये की राशि से उन्होंने मिठाइयां, उपहार और राखी जैसी आवश्यक वस्तुएं खरीदने में मदद मिलेगी। बबीता ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु भैया ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उनके त्योहार की खुशियों को और अधिक बढ़ा दिया है।

बिहान योजना से पेड़ना महिला समूह ने संवारी आत्मनिर्भरता की राह



■ कैटीन संचालन से बढ़ी आमदनी, हर माह 35 से 40 हजार रुपए की आय अर्जित कर रहीं समूह की महिलाएं

■ रक्षाबंधन के पूर्व महतारी वंदन योजना की सहायता राशि देने के लिए विष्णु भैया को दिया धन्यवाद

रायपुर/ संवाददाता

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से मिली सहायता और महिलाओं की मेहनत ने बस्तर जिले की पेड़ना महिला स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भरता की नई राह दिखाई है। समूह की महिलाओं ने छोटी-छोटी बचत से शुरू किया सपर आज कैटीन संचालन से भोजन-जलपान की आपूर्ति तक पहुंच चुका है। समूह द्वारा जनपद पंचायत परिसर तोकापाल में संचालित कैटीन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती मरीजों के लिए भोजन, जनपद पंचायत की बैठकों में चाय-नाश्ता तथा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए भोजन उपलब्ध कराया जा

संपादकीय

देश की राजनीति में आपराधिक मामलों का सामना कर रहे नेताओं को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। इस मुद्दे पर अलग-अलग समय में बहस और चर्चाएं भी होती रही हैं। हालांती में सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में बताया गया कि देश भर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ कर हजार से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। किसी भी समाज में यह उम्मीद की जाती है कि उनके

जनप्रतिनिधि में उच्च स्तर की ईमानदारी, बेवदाग छवि और दूरदर्शी सोच होनी चाहिए। जो एक अच्छा राजनेता उसे कहा जाता है, जो एक व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र और लोगों के समाज के कल्याण को प्राथमिकता दे। मगराज ने यह कई नेता गंभीर आरोपों में घिरा हो, वह जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर जितना खरा उतर पाएगा, इसका अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है।हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में

ब्रताया गया कि देश भर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ चार हजार से अधिक अपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें तीन सौ से ज्यादा सांसद तथा चौदह मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। ऐसे में यह सुवाल उठन स्वाभाविक है कि राजनीति में शुचिता के मानदंडों पर क्या सही मायने में अमल हो पा रहा है? साथ ही इस पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि राजनेताओं के लिए विशेष व्यवस्था के बावजूद उनके

खिलाफ मुकदमे के निपटारे में इतना लंबा वक्त क्यों लग जाता है।

देश की राजनीति में अपराधिक मामले का सामना कर रहे नेताओं को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। इस मुद्दे पर अलग-अलग समय में बहस और चर्चाएं भी होती रही हैं। इसके बावजूद विधायिका में ऐसे जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति बनी हुई है, जिनके खिलाफ कई अपराधिक मामले दर्ज हैं। सवाल सिर्फ मुकदमे जल्दी

पट्टाने का नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध राजनीति में आपराधिक छवि के लोगों को मौजूदगी और जवाबदेही से भीना है। इसमें दो राय नहीं कि किसी व्यक्ति खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होना अलग और उसका अपराध साबित होना दो अलग-अलग बातें हैं। मुकदमे का सामना करने वाले व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना उठारया जा सकता, जब तक उसे अदालत तब से दोषी न करार दिया जाए। मगर सवाल

यह भी है कि जो समाज अपने नेता को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखता है, अगर वह गंभीर आरोपों में घिरा हो, तो उसे किस तरह देखा जाएगा? क्या इससे ईमानदार नागरिकों की शुचिता प्रभावित नहीं होगी? रैजिस्ट्रार का तकाजो तो यही है कि जब किसी जनप्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगें, तो वह विधायी पद से खुद को अलग कर ले, लेकिन आज के समय में ऐसे उदाहरण दुर्लभ हैं।

सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला पर्यटक भारतीय सेना के जवानों के साथ बहस कर रही है और खुद को जेन जेड बताकर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रही है। शायद इस महिला को पता नहीं कि सीमा पर खड़े सैनिक की इयूटी कोई पर्यटन सेवा नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसे किसी पर्यटक की सुविधा, बहस या अधिकारों के नाम पर दरकिनार कर दिया जाए। साथ ही वीडियो में महिला खुद को जेन जेड बताते हुए यह कहती सुनाई देती है कि वह यह बकवास बर्दाश्त नहीं करेगी। यहां सवाल यह उठता है कि क्या किसी पीढ़ी का टैग राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल से ऊपर हो सकता है?

या जेन-जेड होना सुरक्षा नियम तोड़ने का लाइसेंस है?

कारगिल में महिला पर्यटक के आचरण से उठे कई गंभीर सवाल

(नीरज कुमार दुबे)

बताया जा रहा है कि वायलेंट वीडियो में दिखी घटना कारगिल सेक्टर के एक सेवेदनशील हाई-एल्टीट्यूड चेक पोस्ट की है, जहाँ पर्यटकों के एक समूह को प्रतिबंधित दिशा में आगे बढ़ने से रोका गया। बताया जा रहा है कि संबंधित क्षेत्र में प्रवेश के लिए आवश्यक अनुमति और सुरक्षा नियम लागू थे। सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला पर्यटक भारतीय सेना के जवानों के साथ बहस कर रही है और खुद को जेन जेड बताकर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रही है। वायलेंट इस महिला को पता नहीं कि सीमा पर खड़े सैनिक की इच्छाओं के प्रति संवेदन सेवान्वित नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जो जिस किसी पर्यटक की सुविधा, बहस या अधिकारों के नाम पर एक किनार कर दिया जाए। साथ ही वीडियो में महिला खुद को जेन जेड बताते हुए यह कहती सुनाई देती है कि वह यह बकवास सेक्टर नहीं करेगी। यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या किसी पीढ़ी का टैग राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल से ऊपर हो सकता है? बताया जा रहा है कि वायलेंट वीडियो में दिखी घटना कारगिल सेक्टर के एक सेवेदनशील हाई-एल्टीट्यूड चेक पोस्ट की है, जहाँ पर्यटकों के एक समूह को प्रतिबंधित दिशा में आगे बढ़ने से रोका गया। बताया जा रहा है कि संबंधित क्षेत्र में प्रवेश के लिए आवश्यक अनुमति और सुरक्षा नियम लागू थे। एक अन्य विवरण में इसे मिनामागंज में सेमीनारों के चेक पोस्ट के पास अस्थायी सड़क प्रबंधन से जुड़ा बताया गया है। वीडियो में दिख रही तस्वीर बेहद स्पष्ट है। एक तरफ गाँव रहकर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की कोशिश करता वायलेंट और दूसरी तरफ अपनी यात्रा, दूरी और अधिकारों का बखला देकर बहस करता पर्यटक समूह। महिला पथक का यह बर्क कि हम जेन जेड हैं, हम यह सब बहस नहीं करेंगे, दरअसल हम मानसिकता को उजागर करता है जिसमें व्यक्तिगत सुविधा को व्यवस्था और सुरक्षा से ऊपर मान लिया जाता है। जेन जेड होना कोई विशेष सुरक्षा पास है, न ही यह जानूँ है। राशन सुरक्षा प्रोटोकॉल को चुनौती देने का लाइसेंस है। सेना यह नहीं देखती कि मिनामेगंज खड़ा व्यक्ति किस पीढ़ी का है, उसे यह देखना होता है कि मिनामेगंज रहते, कोई संदिग्ध गतिविधि न हो और कोई नागरिक मिनामेगंज में किसी खतरे की जद में न पहुँच जाए। देखा जाये तो कारगिल और नियंत्रण रेखा के आसपास के इलाके सामान्य पर्यटन स्थल नहीं हैं। वह किसी सेवेदनशील भूभाग है जहाँ भारत ने युद्ध का सामना किया है, जहाँ सस्पेंड और आतंकी गतिविधियों का इतिहास रहा है और जहाँ मौसम, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ तथा अन्य गतिविधियाँ हर समय सुरक्षा की अलग चुनौतियाँ पैदा करती हैं। ऐसे में सड़क बंद होना, आवाजाही निर्यंत्रित होना, चेकिंग होना या किसी क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति मांगना कोई एंटी-ट्रस्ट व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जरूरी सुरक्षा व्यवस्था है। सेना और सुरक्षा एजेंसियों को वहाँ इसलिए तैनात रहना पड़ता है क्योंकि सीमावर्ती लाइनों में खतरे केवल दिखाई देते वास्तव नहीं होते। कई बार सुरक्षा नियमों के आधार पर तलाशी या घेराबंदी की जरूरत पड़ सकती है। कभी सैन्य क्राफ्टों को आवाजाही होती है, कभी खराब मौसम या भूखलल के कारण रास्ता असुरक्षित हो जाता है और कभी किसी भीमावित खतरे को देखते हुए नागरिकों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोकी जाती है। ऐसे निम्न किसी एक पर्यटक को

परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि दर्जनों या सैकड़ों लोगों की जाना बचाने के लिए किए जाते हैं। बर्फीली चोटियों, दुर्गम इलाकों और जंगलों में रहने वाले मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है।

गतिविधियाँ भी संभव हो सकें। ऐसे में किसी पर्यटक का जवानों की मदद से पर्यटन में उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुरक्षा बलों के पास मौजूद खुफिया जानकारी, किसी विशेष इन्पुट या चल रहे हथियारों और परेशान का कारण सार्जनिक नहीं किया जा सकता। कई बार सुरक्षा का कारण सार्जनिक नहीं किया जा सकता। कई बार सुरक्षा का कारण सार्जनिक नहीं किया जा सकता।

एक मामूली-सा खुलासा भी सुरक्षा अभियान और जवानों की जाँच में जोड़ सकता है। देश पुनर्वास में सुरक्षा बलों के लिए

प्रवेश का अधिकारपत्र नहीं बन जाती। यदि किसी क्षेत्र के लिए प्रवेश जरूरी है तो पहले उसकी जानकारी लेनी और नियमों का पालन करना पर्यटक की जिम्मेदारी है। विशेष रूप से लद्दाख और अन्य संरक्षित सीमावर्ती क्षेत्रों में नियम प्रस्थितियों और सुरक्षा स्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। सैन्य प्रतिष्ठानों, चेक पोस्टों और रणनीतिक स्थानों पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी भी प्रतिबंधित हो सकती है। इस पूरे प्रणाली का समर्थन चिंतनकार पहले वह भाषा और रवैया है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को व्यवहारा अधिकारों के खिलाफ खड़ा करने की कांशिश दिखाई देती है। लोकतंत्र में सवाल पड़ने का अधिकार है, लेकिन संवेदनशील सैन्य चौकी पर ऑपरेशन या सुरक्षा प्रतिबंध के दौरान



काफिले पर हुए आतंकी हमले की भयावहता देख चुका है और पल्लगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले की त्रासदी भी झेल चुका है। ऐसे अनुभव साफ बताते हैं कि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को लेकर एक छोटी-सी चुक-कुकनी भारी पड़ सकती है। इसलिए पर्यटकों को यह समझना होगा कि जब सेना या सुरक्षा बल किसी रास्ते को बंद करते हैं या आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो हर निर्णय के पीछे की वजह कैमरे के सामने बताना संभव नहीं होता।

ऐसे में जवान से बहस करना, वीडियो बनाना, उस पर अनावश्यक प्रतिक्रियाएँ लगाना का आरोप लगाया या शूरा का व्यवस्थित निराकरण पर सवालिया निशान खड़ा करना केवल अस्वेदनापूर्णता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की गंभीरता को न समझ पाने का उदाहरण होता है। सुरक्षा के मामले में सहयोग और धैर्य ही समझदारी है, क्योंकि सहयोग कई बार जिस खतरे को आम नागरिक देख नहीं सकता, उसे समाप्त करके रोकने के लिए ही जवान वहां खड़ा होता है। साथ ही वायरल हो रहे वीडियो में पर्यटक समूह के कुछ सदस्य यह कहते भी हैं कि इन वीडियो देखते हैं कि वे सैकड़ों किलोमीटर दूर से वहां पहुंचे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को समझना होगा कि लंबी यात्रा किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठापन क्षेत्र में

बहस करके आदेश बदलवाने का अधिकार किसी को नहीं है। समझ, टेक्स या किसी पीढ़ी का नाम लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा को ज़रूरतों को चुनौती देना न तो लोकतंत्र को मजबूत करता है और न ही नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है। दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। जोकि स्वाभाविक है। लोगों ने महिला पर्यटक और उसके साथियों के रवैये को अहकारी और गैर-जिम्मेदाराना बताया है। जैन जेडर वाली टिप्पणी पर मोमस भी बन रहे हैं, लेकिन इस घटना को केवल मनोरंजन के रूप में देखने की बजाय इसमें एक गंभीर सबक लेने की जरूरत है। कैमरे के सामने हंगामा करके वायरल होना आसान है, लेकिन सीमा की सुरक्षा में एक छोटी-सी चूक की भीमत कितनी बड़ी हो सकती है, इसका अंदाजा वहां तैनात जवानों को हमसे नहीं बेहतर है। यह चेतावनी केवल उन महिला पर्यटकों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया की लोकप्रियता, व्यक्तिगत सुविधा या पीढ़ीगत पहचान के नाम पर सुरक्षा नियमों को हल्के में लेते हैं। शाह की सुरक्षा किसी हैशटैग, नारे या वायरल वीडियो के हिस्से नहीं चल सकती। सीमा पर तैनात सैनिकों को अपना काम करने दीजिए।

जनगणना में सिर्फ आबादी नहीं, बदलती जलवायु का हिसाब भी जरूरी

(कुशाग्र राजेंद्र)

आज भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, वे केवल सामाजिक या आर्थिक नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन अब भीषण की आशंका नहीं, वर्तमान की वास्तविकता है। देश एक बार फिर जनगणना की तैयारी में है। लम्बे अंतराल के बाद होने वाली यह जनगणना स्वाभाविक रूप से अनेक प्रश्नों के केंद्र में है। क्या इसमें जातिगत गणना होगी? इससे कल्याणकारी योजनाओं और राजनीतिक प्रतिस्पर्धित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राज्यों को संसाधनों का बंटवारा किस आधार पर होगा? ये सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं और लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा भी, लेकिन इनके बीच एक बुनियादी सवाल लगभग अनुपस्थित है और यह कि क्या इसीसवीं सदी की जनगणना उन वास्तविकताओं को दर्ज करने के लिए तैयार है, जिनका सामना आज का भारत कर रहा है? जनगणना प्रायः केवल जावदी गिनने की प्रक्रिया मानी जाती है। जबकि यह किसी भी राष्ट्र की प्रशासनिक दृष्टि का दर्पण होती है। कोई भी सरकार जिन बातों को जानना आवश्यक समझती है, वही उसके प्रश्नों में दिखाई देती हैं। इसलिए जनगणना केवल यह नहीं बताती कि देश में कितने लोग हैं, बल्कि यह भी बताती है कि राज्य अपने समाज को किस नजर से देख रहा है और भीषण की चुनौतियों को किस प्रकार समझना चाहता है। स्वतंत्र भारत की जनगणना समय के साथ बदलती रही है। आवास, पेयजल, शौचालय, बिजली, रोजी ईंधन, बैंकिंग सुविधा, मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसी जानकारीयें हमें क्रमशः जुड़ती गईं। इनसे शासन को विकास योजनाएं बनाने, सामाजिक असमानताओं को समझने और कल्याणकारी कार्यक्रमों को लक्षित करने में बड़ी सहायता मिली। इसमें कोई संदेह नहीं कि आधुनिक भारत के निर्माण में जनगणना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, वे केवल सामाजिक या आर्थिक नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन अब भीषण की आशंका नहीं, वर्तमान की वास्तविकता है। उत्तर भारत में तीव्र हो रही लू, भीषण गर्मी, पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली गिरने की बढ़ती घटनाएं, असम और बिहार में बार-बार होने वाली बाढ़ें, बुंदेलखंड और दक्षिण में गहराता जल संकट, हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमदण्ड झीलों के फटने का खतरा तथा पश्चिमी भारत में भूजल का लगातार गिरता स्तर, ये सभी घटनाएं

भारत अलग-अलग परिवारणीय सम्प्रदायों में अलग-अलग सीधा असर देखते हैं। गोजार, स्वास्थ्य, पलायन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इस पंथीयता से विचार करने की जरूरत है। विभेदना यह है कि इन परिवर्तनों का सम्बन्धने के लिए हमारे पास अलग-अलग विभागों में बहुत-सी सूचनाएँ उपलब्ध हैं। लेकिन वे एक-दूसरे से जुड़ती नहीं हैं। मौसम का आँकड़ा एक संस्था के पास है। भूजल का दूसरे के पास, कृषि का तीसरे के पास और जनसंख्या का चौथे के पास। परिणाम यह है कि हमें यह तो पता है कि किस गाँव में कितने परिवार रहते हैं, लेकिन यह व्यवस्थित रूप से नहीं पता कि सुखते तालाब, घटता भूजल बदलती फसलें या बार-बार आने वाले अपदाएँ वहाँ के लोगों के जीवन और आजीविका को किस प्रकार बदल रही हैं। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में सम्प्रदाय केवल आँकड़ों की कमी नहीं है। सम्प्रदाय यह है कि हमारे पास जीवन और पर्यावरण को एक साथ देखने वाले सूचना व्यवस्था नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के प्रशासनिक इतिहास में ऐसी सम्प्रदाय दृष्टि के उदाहरण पहले से मौजूद हैं। इसका उदाहरण 1887 में तत्कालीन मराठावाड़ राज्य में जनगणना के लिए तैयार की गई ग्राम प्रश्नावली है। यह केवल गाँव की आबादी या राज्यस्तर के ब्योरा भर नहीं मांगती थी। इनमें कुल और तालाबों की संख्या, पानी की गुणवत्ता, मिट्टी का प्रकार, चरगाहा, वृक्षों की प्रजातियाँ, पशुधन, स्थानीय फसलें, कुटीर उद्योग, महामारी, अकाल, पलायन, स्थानीय धरोहर और गाँव की सामाजिक संस्थाओं तक का विवरण दर्ज करने के 56 प्रश्न थे। गाँव को केवल घरों के समूह के रूप में नहीं, बल्कि मनुष्य, प्रकृति और स्थानीय संस्थाओं से मिलकर बने एक जीवंत तंत्र के रूप में देखा गया था। उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के प्रारंभिक दशकों में तैयार अनेक जिले, जेजेटियर और ग्राम अपडिलेखों में वर्षा, नदियाँ, जंगल, मिट्टी, सिंचाई, पशुधन, स्थानीय उद्योग तथा प्राकृतिक संसाधनों यहाँ तक कि रीति-रिवाज, खान-पान तक का विवरण जनसंख्या संबंधी सूचनाओं के साथ मिलता है। निस्संदेह इन्हीं दस्तावेजों का उद्देश्य औपनिवेशीय प्रशासन, राजस्व निर्धारण और अकाल प्रबंधन था, पर्यावरण संरक्षण नहीं। फिर भी उन्होंने गाँवों का ऐसा सामाजिक पर्यावरणीय चित्र सुसुलित कर दिया, जो आज जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मूल्यवाना स्रोत बन गया है।

‘वंदे मातरम्’ के अपमान से कांग्रेस के तुष्टिकरण की पोल खुली, नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक एक ही पैटर्न?

‘वंदे मातरम्’ के हाल ही में किए गए अपराध और अपमान के संदर्भ में कांग्रेस के प्रवक्ता और आधिकारिक व्यक्तित्व जो कह रहे हैं उसमें वे गांधी जी, नेताजी सुभाषचंद्र, गुरुदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर आदि का नाम लेते हुए इस गीत के विभाजन को उनकी सेहुआ बता रहे हैं। यह एक भ्रमजाल और झूठ का पहाड़ है। गांधी जी तो इस बात के पक्षधर थे कि यह गीत संपूर्ण देश को जोड़ने वाला प्राणतत्त्व है और इसे इसके पूर्ण वैभव के साथ संपूर्णतः स्वीकार किया जाना चाहिए।

(प्रवीण गुप्ताजी)

‘वैदे मातरं’ के हाल ही में किए गए अपराध और अपमान के संदर्भ में कांग्रेस के प्रवक्ता और आधिकारिक व्यक्तित्व जो कह रहे हैं उसमें वे गांधी जी, नेताजी सुभाषचंद्र, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर आदि का नाम लेते हुए इस गीत के विभाजन को उनकी से हुज्र बना रहे हैं। यह एक भ्रमजाल और झूठ का पहाड़ है।

एक बंगाली कहावत है - मायेर स्तवेर अर्पेक प्रणय, अर्पेक बर्जन, ए कैमन सन्तानेरे भाकि। मातृभूमि के स्तुति गीत को आधा स्विकारना और आधा त्यागना, यह किस प्रकार की संतान की भाँक है? भद्र बंगाल की सौ वर्षों की व्यथा, वेदना ही इस लोकोक्ति रूप में प्रकट हुई है। भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम का शायद ही कोई दूसरा गीत वदे मातरम् जितना भावात्मक, राजनीतिक और ऐतिहासिक रहा हो। बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय जी की यह रचना केवल साहित्य नहीं अपितु वह स्वदेशी आन्दोलन, क्रांतिकारियों और राष्ट्रीय जगरण का उद्घाटन बनी थी। 15 अगस्त, 2026 को कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में कारित धृष्टत कृत्य से कांग्रेस का इस्तीफाक डीनए पुनः सिद्ध हो गया है। वैदे मातरम् के इस अपमान के समय नेता प्रतिपक्ष रहलू गांधी, दासक भर कांग्रेस अच्यख रही सोनिया गांधी और कांग्रेस अच्यख खड्डो उपनिथत थे। दुस्साहस और दुर्भाग्य का विषय है है कि इन तीनों ने ही वदे मातरम् के अपमान के इस दुकृत्य को प्राप्थ किया था। इस दुर्भाग्यजनक घटना के बाद कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं ने देश को स्पष्टीकरण देना प्राप्थ किया कि - सोनिया गांधी ने वदे मातरम् का प्राप्थ नहीं किया बल्कि वे बुजुर्ग खड्डो जी को खड्डो होने के कारण असज्ज होता देखकर उनको लिए कुर्सी मंगा रही थी। यहीं से कांग्रेस नेतृत्व की मुझता, राड अन्याया व मुस्लिम तुष्टिकरण के पक्ष में दुराग्रह रखने के चरित्र की पुनरुवृत्ति दिखई पडती है। इस घटनाक्रम के अंतरतल को समझिए। कांग्रेस के

जमीनी कार्यकर्ताओं को अपने नेतृत्व द्वारा 'वे मातर' का यह अपमान बुरा लगा इसलिए ही उन्होंने बिना केंद्रों के या प्रेशे नेतृत्व के कहे ही इस घटना पर काँग्रेस नेतृत्वलक्ष्य का बचाल प्रारंभ कर दिया था। हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर तारुण्य पेशे इतनी और काँग्रेस नेतृत्व का बचाव किया। यह 'वे मातर'।



और 'मुस्लिम तृष्टिकरण की काँग्रेसी प्रवृत्ति' के विरोध का प्रतीक था। इस मनोभाव को कांग्रेस के इटालियन नेतृत्व ने समझने का प्रयास ही नहीं किया। कांग्रेस ने इस घटना पर अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नहीं समझा तो भी कोई ज्ञात नहीं होता कांग्रेस ने तो अपनी दृष्टिधर्मिता, अडिक्लिपता, मूल मुद्दा की हद तो बंद रखी। वह जब उसमें अपनी राष्ट्रीय वकिंग कमेटी 'वन्दे मातरम्' को पूर्ण रूप में नहीं गाने के लिए प्रस्ताव ही पारित कर दिया। 'वन्दे मातरम्' के हाल ही में किए गए अपराध और अपमान के संदर्भ में कांग्रेस के प्रवक्ता और आधिकारिक व्यक्तित्व जो कह रहे हैं उसमें वे गांधी

जी, नेताजी सुभाषचंद्र, गुरुदेव रबिन्द्रनाथ ठगोर आदिदिवसों का नाम लेते हुए इस गीत के विभाजन को उनकी से हटा हुआ बता रहे हैं। यह एक भ्रमजाल और झूठ का पहाड़ है। गांधी जी तो इस बात के पक्षधर थे कि यह गीततत्त्व संपूर्ण देश को जोड़ने वाला प्राणतत्त्व है और इसे इसके पूर्ण वैभव के साथ संपर्कित: स्वीकार किया जाना

गान्धर्वम्

चाहिए। गांधी जी ने इसके समर्थन में अपनी स्पष्ट राय रखी थी, किंतु जवाहरलाल नेहरू ने तृप्तिकर्ता की अपनी राजनैतिक कुटिलताओं और प्राथमिकताओं के चलते गांधी जी को एक न चले दी। इतिहास यह भी है कि, यह दुःखद एतिहासिक पृष्ठ रहस्यमयी भी है। रहस्य यह कि - अंततः वह कौन सी कमजोरी नस थी, जिसके आधार पर - अंततः गांधी जी ऐसे निर्णय भी गांधी जी से करवा लेते थे जिनके लिए गांधी जी कभी भी तैयार नहीं थे। गांधी जी वंदेमातरम् विभाजन हेतु असहमत थे। गांधी जी की बंग-ध्वज हेतु भी सहमत नहीं थे। गांधी जी ने कहा था कि इस देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। गांधी जी

भी स्वतंत्रता पश्चात् कांग्रेस को विस्तारित करने हेतु भी सकल्पित थे। गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता पश्चात् हम एक बूँद की स्याही लेंगे और यह लिख देंगे - 'सर्व देश में गौहत्या वैसा ही दंड होगा जैसा मानव हत्या के लिए होता है।' स्पष्टतः, हिंदी राष्ट्रप्राप्ति, ग्रामवासी भारत आदि हेतु भी गांधी जी प्रविष्ट थे। कांग्रेस ने सतत उसके को सता में इन विषयों को त्याज्य रखा। 'भारत में रामराज स्थापना' को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया था किन्तु 'नेहरू-गांधी कांग्रेस' मुस्लिम नृत्तिकरण के लिए श्रीराम को ही कल्पना सिद्ध करने के प्रयास में लग गई। कांग्रेस स्वयं को सेकुलर सिद्ध करने के अनेक प्रयास करने लगी थी और 'रामेश्वरम् रामसेतु' के विच्छेद, विनाश, भंजन, खंडन हेतु भरीनीं समुद्रतट पर भेजे चुकी थी। 'मुस्लिम नृत्तिकरण' हेतु कांग्रेस ने न जितने ही कांड इस देश में किया और सतत-निरंतर किए। आश्रय और दुस्सास का विषय यह है कि 'मुस्लिम नृत्तिकरण' के लिए देश भर से लाटड़े जाने के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व इस बात को समझ ही नहीं रहा है। हाँ, कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता इस बात कोई समझ भी रहा है और यह कांग्रेस को 'मुस्लिम नृत्तिकरण' की नीति के विरोध में भी है, तब ही तो 'कार्यकर्ता बेचारे' ने सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में आकर यह कहा था कि सोनिया जी वंदे मातरम् का गान रोक नहीं रही थी बल्कि खड़ो जी के लिए कुर्सी बुला रही थी। 'वंदे मातरम्' और 'मुस्लिम नृत्तिकरण' की यह काँग्रेस कार्यकर्ता की नैसर्गिक प्रतिक्रिया थी जिसे कांग्रेस नेतृत्व ने स्वीकार करना चाहिए थे किन्तु कांग्रेस ने 'राम पथ' को नहीं बल्कि 'राम पथ' को चुना हुआ है। 26 अक्टू- 1 नव. 1937 की कलकत्ता कांग्रेस कार्यसमिति में 'वंदे मातरम्' गान के विभाजन की अनुरंश का एक कुछ नहीं बल्कि एक 'इमोशनल शायर' ब्लैकमे' था। यह देश विभाजन में अपना हित देखने वाले नेताओं द्वारा निर्मित 'ब्लैकमे' था।

संक्षिप्त समाचार

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे,
बिलासपुर में नए श्रम कानूनों
पर कार्यशाला आयोजित



बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कार्मिक विभाग, मुख्यालय द्वारा आज एनईआई सभागृह, बिलासपुर में नए श्रम कानूनों जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय एवं बिलासपुर मंडल के प्रधान विभागाध्यक्षों एवं अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यशाला में मुख्य अतिथि श्री विजय कुमार साहू, अपर महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे तथा मुख्य वक्ता श्री डॉक्टर एच. श्रीनिवास (आईआरपीएस) रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी डॉ. दर्शनीता बी. अहलुवालिया द्वारा मुख्य वक्ता श्री एच. श्रीनिवास का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया तथा मुख्य अतिथि श्री विजय कुमार साहू का भी स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि श्री विजय कुमार साहू ने अपने स्वागत उद्बोधन में नए श्रम कानूनों के महत्व एवं वर्तमान संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मुख्य वक्ता श्री एच. श्रीनिवास के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता श्री डॉक्टर एच. श्रीनिवास (आईआरपीएस) ने नए श्रम कानूनों की विस्तृत विवेचना करते हुए उनके प्रमुख प्रावधानों एवं मूल तथ्यों को सरल एवं सहज भाषा में उपस्थित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए विषय की व्यावहारिक समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नए श्रम कानूनों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन एवं बेहतर समझ को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम के सफल समापन पर मुख्य वक्ता श्री डॉक्टर एच. श्रीनिवास के प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

बिलासपुर यलहंका (बेंगलुरु)
बिलासपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस
का नियमित परिचालन शुरू

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा बिलासपुर से दक्षिण भारत के बीच रेल संपर्क को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिलासपुर यलहंका (बेंगलुरु) बिलासपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस (18261/18262) का नियमित परिचालन आज 26 अगस्त 2026 से प्रारंभ किया गया। यह रेल सेवा दोनों क्षेत्रों के बीच शिक्षा, रोजगार, व्यापार, उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक संपर्क को भी नई गति प्रदान करेगी। विशेष रूप से बेंगलुरु जैसे प्रमुख आईटी एवं औद्योगिक केंद्र से बिलासपुर क्षेत्र का सीधा रेल संपर्क मजबूत होने से विभिन्न वर्गों के यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस ट्रेन के साप्ताहिक नियमित परिचालन के अंतर्गत गाड़ी संख्या 18261 बिलासपुर- यलहंका (बेंगलुरु) साप्ताहिक ट्रेन बिलासपुर से दिनांक 26 अगस्त 2026 से प्रत्येक बुधवार को एवं इसी प्रकार गाड़ी संख्या 18262 यलहंका (बेंगलुरु) बिलासपुर साप्ताहिक ट्रेन यलहंका से दिनांक 27 अगस्त 2026 से प्रत्येक गुरुवार को चलाई जाएगी। गाड़ी की समय-सारिणी गाड़ी संख्या 18261 बिलासपुर- यलहंका (बेंगलुरु) साप्ताहिक ट्रेन 26 अगस्त 2026 से प्रत्येक बुधवार को बिलासपुर से 14.00 बजे रवाना होगी तथा भाटापारा आगमन 14.40 बजे, प्रस्थान 14.42 बजे, रायपुर आगमन 15.35 बजे, प्रस्थान 15.40 बजे, दुर्ग आगमन 16.25 बजे, प्रस्थान 16.30 बजे, राजनादगाँव आगमन 16.49 बजे, प्रस्थान 16.51 बजे, डोंगरगढ़ आगमन 17.12 बजे, प्रस्थान 17.14 बजे, गोंदिया आगमन 18.15 बजे, प्रस्थान 18.25 बजे, वडसा आगमन 19.32 बजे, प्रस्थान 19.34 बजे, चांदाफेर्ट आगमन 21.18 बजे, प्रस्थान 21.20 बजे, बल्लारशाह आगमन 22.05 बजे, प्रस्थान 22.15 बजे, सिरपुर कागजनगर आगमन 22.59 बजे, प्रस्थान 23.00 बजे, मॉचर्याल आगमन 23.54 बजे, प्रस्थान 23.55 बजे, दूसरे दिन काजीपेट आगमन 01.38 बजे, प्रस्थान 01.40 बजे, चर्लपल्ली आगमन 03.08 बजे, प्रस्थान 03.10 बजे, सिकंदराबाद आगमन 05.55 बजे, प्रस्थान 06.05 बजे, लिंगमपल्ली 06.18 बजे, प्रस्थान 06.20 बजे, विकाराबाद आगमन 07.03 बजे, प्रस्थान 07.05 बजे, तांडूर आगमन 07.43 बजे, प्रस्थान 07.45 बजे, यादगिरि आगमन 09.13 बजे, प्रस्थान 09.15 बजे, कृष्णा जंक्शन आगमन 09.50 बजे।

निवारक सतर्कता अभियान के अंतर्गत एसईसीएल
मुख्यालय में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम...

■ बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री राम गोपाल गर्ग ने अधिकारियों कर्मचारियों को किया साइबर अपराधों से सतर्क

■ बिलासपुर पुलिस ने किया ‘साइबर जागृति रक्षा सूत्र अभियान’ का शुभारंभ

बिलासपुर। साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) मुख्यालय, बिलासपुर में केंद्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शन में एसईसीएल में संचालित तीन माह के सतर्कता निवारक अभियान के अंतर्गत आज साइबर सुरक्षा

जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ पुलिस के ‘साइबर जागृति अभियान’ के साथ समन्वय करते हुए साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, डिजिटल सुरक्षा के प्रति सतर्कता विकसित करने तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया। इस अवसर पर बिलासपुर पुलिस द्वारा ‘साइबर जागृति रक्षा सूत्र अभियान’ का शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम में भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, श्री राम गोपाल गर्ग मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। बिलासपुर के उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एसईसीएल के निदेशक (तकनीकी/संचालन) श्री एन. फ्रैंकलिन जयकुमार, निदेशक (मानव



संसाधन) श्री बिरंकी दास तथा निदेशक (तकनीकी/योजना एवं परियोजना) श्री रमेश चंद्र महापात्र सहित कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में श्री राम गोपाल गर्ग ने साइबर अपराधों के बदलते स्वरूप और उनसे बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने फिशिंग, फर्जी लिंक, ओटीपी एवं

केवाईसी प्रॉड, सोशल मीडिया आधारित साइबर अपराधों तथा ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विभिन्न तरीकों की जानकारी देते हुए डिजिटल लेन-देन के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की, साइबर ठगी की रीतिथि में तत्काल 1930 हेल्पलाइन अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने का आग्रह किया। श्री गर्ग ने ‘साइबर जागृति

रक्षा सूत्र अभियान’ की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि साइबर सुरक्षा केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी भी है। विशिष्ट अतिथि श्री रजनेश सिंह ने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम में जन-जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन का उपयोग करते समय सावधानी बरतने तथा किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर बिना विलंब 1930 हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की। एसईसीएल में संचालित तीन माह के सतर्कता निवारक अभियान के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा को सुशासन, पारदर्शिता और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार के महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में रेखांकित किया गया।

पीएम आवास योजना में
फर्जीवाड़ा मामला: तिलकेजा
पंचायत सचिव को नोटिस

कोरबा। जनपद पंचायत कोरबा के अंतर्गत आने वाले सांसदआदर्श ग्राम पंचायत तिलकेजा में प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जी हितग्राहियों के नाम से राशि जारी करवा कर उसका बंदरबांट करने के मामले में तिलकेजा की पंचायत सचिव नविता दुबे को निर्लांबित कर दिया गया है। विकासखंड समन्वयक देवानंद श्रीवास वरुन से हटकर जनपद में अटैच करने की कार्रवाई की गई है। बता दें कि इस मामले में की गई शिकायत में 48 लोगों के नाम से फर्जीवाड़ा का गंभीर आरोप लगाया गया। आरटीआई अधिककर्ता जितेंद्र साहू के द्वारा की गई शिकायत के बाद मामले में जांच हेतु जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन (आईएसएस)

द्वारा टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा जांच के सिलसिले में सचिव श्रीमति नविता दुबे को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश जारी किया गया। सरपंच/सचिव को 48 हितग्राहियों का राशि जिनके खाते में गया उनका आधार कार्ड, बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी रजिस्टर लेकर दिनांक 13.08.2026 को कार्यालय उप सचिवक पंचायत जिला कोरबा में उपस्थित होने कहा गया था किंतु सरपंचध्वजिच उपस्थित नहीं हुए। इसी तरह श्रीमती नविता दुबे सचिव ग्राम पंचायत तिलकेजा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर 03 दिवस के भीतर जवाब चाही गई थी

रेल संरक्षा के 09 सजग प्रहरियों को महाप्रबंधक ने किया सम्मानित

बिलासपुर। रेल परिचालन में संरक्षा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सजगता एवं बेहतर संरक्षा कार्य में सहभागिता निभाने वाले रेल संरक्षा के सजग प्रहरी कर्मचारियों का सम्मान महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा हर माह आयोजित संरक्षा बैठक के दौरान किया जाता है। इसी कड़ी में आज दिनांक 25 अगस्त, 2026 को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कार्यरत संरक्षा कोटि के 09 कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट एवं सराहनीय संरक्षा संबंधी कार्य निष्पादन के लिए महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश के द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सम्मानित किए गए कर्मचारियों के सराहनीय कार्य इस प्रकार हैं:- लोको पायलट, गुड्स के पद पर कोरबा में पदस्थ कर्मचारी श्री धीरेंद्र कुमार द्विवेदी ने ड्यूटी पर जाते समय कोरबा यार्ड की बालिन नंबर-4 के पास रेल फ्रैक्टर की पहचान कर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। समय पर कार्रवाई से ट्रैक को संरक्षित कर रेल परिचालन सुचारु रूप से सुनिश्चित किया गया। स्टेशन मास्टर के पद

पर उरगा में पदस्थ कर्मचारी श्री शशिकांत कुमार सिंह ने मालगाड़ी से ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करते समय इंजन से 15वें वैगन में ब्रेक बाईडिंग की पहचान कर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। समय पर कार्रवाई से गाड़ी का संरक्षित संचालन सुनिश्चित किया गया। लोको पायलट, गुड्स के पद पर शहडोल में पदस्थ कर्मचारी श्री अविनाश कुमार ने मालगाड़ी में जामगा स्टेशन की ओर जाते समय भारी झटका महसूस होने पर गाड़ी रोककर रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। रेल सतह पर रिक्रड के निशान की पहचान कर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। समय पर कार्रवाई से गाड़ी का संरक्षित संचालन सुनिश्चित किया गया। तकनीशियन ग्रेड-1 के पद पर बिलासपुर में पदस्थ कर्मचारी श्री संतोष कुमार सिंह ने बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफर्म नंबर-3 से गुजर रही मालगाड़ी के रोलिंग-आउट निरीक्षण के दौरान 22वें वैगन की असामान्य स्थिति की पहचान कर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। समय पर कार्रवाई से वैगन को संरक्षित



रूप से रीरेल कर गाड़ी का पुनः संचालन सुनिश्चित किया गया। ट्रैक मेंटेनर-ड्रुड के पद पर तिल्दा में पदस्थ कर्मचारी श्री तुलाराम डहरिया ने ड्यूटी के दौरान एसईजे टंग रेल में फ्रैक्टर की पहचान कर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। समय पर कार्रवाई से ट्रैक को संरक्षित कर रेल परिचालन सुचारु रूप से सुनिश्चित किया गया। स्टेशन मास्टर के पद पर दाधापारा में पदस्थ कर्मचारी श्री मनोज कुमार रजक ने ड्यूटी के दौरान रिले/बैटरी कक्ष में अग्नि अलार्म सक्रिय होने पर तत्काल स्थिति का संज्ञान लेते हुए प्रभावी कार्रवाई की। उनकी तत्पता एवं सूझबूझ

से समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर रेल परिसंपत्तियों को संरक्षा सुनिश्चित की गई। वरिष्ठ तकनीशियन (यांत्रिक) के पद पर दुर्ग में पदस्थ कर्मचारी श्री भारत ने वंदे भारत ट्रेन संख्या 20829/30 के डेली शेड्यूल परीक्षण के दौरान पैंटोग्राफकार्बन स्ट्रिप में बारीक दरा की पहचान कर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। समय पर कार्रवाई से ट्रेन का संरक्षित संचालन सुनिश्चित किया गया। कनिष्ठ अभियंता/रेलपथ के पद पर कन्हान में पदस्थ कर्मचारी श्री उदय कुमार ने टीडब्ल्यूएस/एसईजे नवीनीकरण कार्य की निगरानी के दौरान चाचर स्टेशन से

गुजर रही मालगाड़ी के एक वैगन के नीचे घिसटती एमएस बेस प्लेट की पहचान कर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। समय पर कार्रवाई से बेस प्लेट को हटाकर गाड़ी का संरक्षित संचालन सुनिश्चित किया गया। वरिष्ठ सहायक लोको पायलट के पद पर नागपुर में पदस्थ कर्मचारी श्री कुणाल तुलसीराम चित्तगोरे ने शिवनाथ एक्सप्रेस से ड्यूटी के दौरान समानांतर पटरी पर चल रही मालगाड़ी के एक वैगन की असामान्य स्थिति की पहचान कर तत्काल की-टॉकी के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। समय पर कार्रवाई से संबंधित वैगन को अलग कर गाड़ी का संरक्षित संचालन सुनिश्चित किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक ने कहा कि रेल परिचालन में संरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और कर्मचारियों की ऐसी सजगता एवं कर्तव्यनिष्ठा अन्य रेलकर्मियों के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने सभी को भविष्य में भी इसी उत्साह और समर्पण के साथ कार्य करने की शुभकामनाएं दीं।

राखी के पर्व पर बहनों की तरक्की
की मिसाल बनीं लखपति दीदियां

ऑपरेशन नारकोस के तहत रेलवे
सुरक्षा बल,गोंदिया की कार्रवाई



रखा है। संयंत्र में उत्पादन को व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए फीड ग्राइंडर एवं मिक्सर मशीन, फीड पैलेट मशीन तथा फीड क्रम्बल मशीन स्थापित की गई हैं। इन मशीनों के माध्यम से विभिन्न प्रक्रियाओं को सुगम बनाकर पशु एवं पक्षी आहार तैयार किया जा रहा है। बिहान योजना के माध्यम से महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक रूप

से सशक्त बनाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में जय भारत महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने पशु आहार निर्माण को आजीविका का माध्यम बनाया है। समूह की महिलाएं संयंत्र के संचालन, पशु आहार निर्माण, पैकेजिंग और अन्य कार्यों में सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रही हैं। बिलासा पशु आहार संयंत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रहा है। पशुपालन एवं कुकूट पालन से जुड़े ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही पशु एवं पक्षी आहार मिलने से समय और परिवहन लागत में सुविधा हो रही है। यह पहल अन्य महिला स्व सहायता समूहों के लिए भी प्रेरणा बन रही है।

बिलासपुर। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन नारकोस के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में रेलवे सुरक्षा बल गोंदिया की अपराध गुप्तचर शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 02 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्करो को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 69 पैकेट में कुल 72.661 किलोग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत ₹36,33,050/- है, बरामद किया गया। दिनांक 24 अगस्त 2026 को प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर रेलवे सुरक्षा बल फ्राइम टीम, गोंदिया के अधिकारी एवं बल सदस्यों ने गाड़ी संख्या 22827 पुरीसूरत एक्सप्रेस में दरेकसागोंदिया के मध्य कार्रवाई की। टीम ने कोच संख्या क्र-5 में यात्रा कर रहे एक महिला एवं एक पुरुष यात्री को चार ट्रॉली बैग के साथ सौंदिध अवस्था में पकड़ा। पृष्ठताछ में दोनों ने अपना नाम टूकु नायक, उम्र 38 वर्ष तथा ईश्वरी बेहरा उर्फ इशू, उम्र 35 वर्ष, निवासी काटाभाजी, बलांगीर (ओडिशा) बताया। विधिवत तलाशी लेने पर उनके चारों ट्रॉली बैग से 69 पैकेट गांजा, कुल वजन 72.661 किलोग्राम, बरामद हुआ। प्रारंभिक पृष्ठताछ में आरोपियों ने बताया कि उक्त गांजा काटाभाजी,



ओडिशा से ट्रेन के माध्यम से भुसावल, महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। पृष्ठताछ के दौरान आरोपियों द्वारा पूर्व में भी लगभग 10 बार गांजा तस्करी किए जाने की जानकारी दी गई। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार आरोपियों के विरुद्ध ओडिशा के विभिन्न स्थानों में पूर्व के आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होना पाया गया। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए दोनों आरोपियों को बरामद गांजा सहित अग्रिम कार्रवाई के लिए जीआरपी गोंदिया के सुपुर्द किया गया।

भोजली पर्व को देशभर में पहचान दिलाने का
प्रयास,परंपरा बचाने महिलाओं ने उठाया बीड़ा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की विलुप्त होती लोक परंपराओं और तीन-त्योहारों को नई पीढ़ी से जोड़ने के उद्देश्य से भोजली पर्व का आयोजन लगातार विस्तार ले रहा है। आयोजकों का कहना है कि भोजली केवल एक पर्व नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सामाजिक एकता, भाईचारे, प्रेम और आपसी संबंधों को मजबूत करने वाली परंपरा है। इसे जीवंत रखने और देशभर में इसकी पहचान बनाने के लिए वर्षों से प्रयास किया जा रहा है। अगुवाई जन कल्याण समिति बिलासपुर के संयोजक विष्णु यादव, दीपमाला गुप्ता, देवनागरण साहू, राजू यादव, राखी यादव, मनोरमा यादव, पप्पू टाकुर ने प्रेस क्लब में हमर पहुँना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान युवा पीढ़ी धीरे-धीरे अपनी पारंपरिक संस्कृति और पर्वों से दूर होती जा रही है। ऐसे में भोजली जैसे आयोजनों के माध्यम से उन्हें अपनी कड़ों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भोजली पर्व में महिलाओं की टोलियां



उत्साहपूर्वक शामिल होती हैं और आपस में मितान , मिआ तथा महाप्रसाद बांटने की परंपरा निभाती हैं। आयोजकों ने इसे छत्तीसगढ़ का पारंपरिक ‘फ्रेंडशिप डे’ बताते हुए कहा कि इस पर्व में आपसी प्रेम, मित्रता और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी संस्कृति के विभिन्न दिवसों के बीच अपनी लोक परंपराओं को भी पहचान दिलाने की जरूरत है। भोजली के माध्यम से महिलाओं, युवतियों और युवाओं को एक-दूसरे से जोड़ने तथा पुरखों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आयोजन में प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं

और आकर्षक पुरस्कार दिए जाते हैं, ताकि लोगों में उत्साह बना रहे और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें। गांव-गांव तक पहुंच रहा भोजली का संदेश- आयोजकों के मुताबिक भोजली आयोजन का प्रचार-प्रसार पिछले कई वर्षों से व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए गांवों की सूची तैयार कर ऑटो के माध्यम से प्रचार कराया जाता है। इसके बाद विभिन्न गांवों से महिलाओं की टोलियां भोजली लेकर आयोजन स्थल तक पहुंचती हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में अरपा नदी किनारे आयोजन के लिए बड़ा स्थान मिलने के बाद भोजली पर्व का स्वरूप और अधिक व्यापक हुआ।

एनर्जी के लिए ब्लॉक कॉफी- सुबह की दिनचर्या का आखिरी स्टेप होता है जिसमें वो सुबह एक कप ब्लॉक कॉफी लेती है, जिसे वह नाश्तल तेल पीने के पीती है। ब्लॉक कॉफी उन्हें दिन भर अधिक एनर्जेटिक और आराम रहने में मदद करती है।

न्यूट्रिशनशट ने बताया कि ब्लॉक कॉफी पीने से शरीर में सुबह के समय कोर्टिसोल के नेचुरल लेवल को 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं, इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और आप कहीं ज्यादा एक्टिव रहते हैं। कॉफी में

पॉलीफेनॉल होते हैं, जो ऐसे योगिक हैं, जो आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं।

रात को गोवंशों को रिफ्लेक्टर पहनाकर हटाया, सुबह फिर सड़कों पर जमावड़ा, मालिकों पर कार्रवाई जरूरी

अंजोरा से लेकर पेंड्री, नंदई चौक, भदौरिया चौक, बसंतपुर रोड, इंदिरा नगर पर समस्या



गोवंशों से सीधे मालिकों की पहचान जरूरी, ठोस कदम से रूकेमे हदसे, सख्ती होनी चाहिए

राजनांदगांव। नेशनल हाइवे पर 11 गोवंशों की मौत के बाद यह तो साफ था कि अब प्रशासनिक अमला हरकत में आएगा और हुआ भी ठीक वैसा ही। सोमवार रात से ही टीम सड़क पर दिखने लगी। रोड पर बैठे गोवंशों को हटया गया, उनके गले में रिफ्लेक्टर लगाया गया। लेकिन इसके ठीक दूसरे दिन यानी मंगलवार को सुबह से लेकर रात का नजारा

नियमित किराया जमा नहीं करने और व्यवसाय बंद रखने पर निगम की कार्रवाई

गौरव पथ स्थित एलआईसी कार्यालय के सामने 8 गुमटियां सीलबंद, निगम ने कब्जे में लिया

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा निगम सीमा क्षेत्र में आवंटित गुमटियों से नियमित किराया वसूली तथा उनका निर्धारित उद्देश्य के अनुसार संचालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गौरव पथ रोड स्थित एलआईसी कार्यालय के सामने आवंटित गुमटियों में नियमित किराया जमा नहीं करने एवं गुमटियों में व्यवसाय संचालित नहीं किए जाने के कारण संबंधित आवंटितों को पूर्व में नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी किए जाने के बावजूद संबंधित आवंटितों द्वारा निर्धारित अवधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही किराया जमा करने तथा व्यवसाय संचालन के



संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई। इसे गंभीरता से लेते हुए नगर निगम द्वारा कुल 8 गुमटियों को सीलबंद कर निगम कब्जे में ले लिया गया। नगर निगम द्वारा सीलबंद की गई गुमटियों में गुमटी क्रमांक 04 के आवंटित चुन्नीलाल सिन्हा, क्रमांक 07 के प्यारेलाल बोरकर, क्रमांक 09 के मिश्रलेश ठाकुर, क्रमांक 19

के पूरनलाल कसार, क्रमांक 20 के राजकुमार चारे, क्रमांक 22 के शेष गणपार, क्रमांक 23 के सान मोहम्मद तथा क्रमांक 24 के विजय कुमार विश्वकर्मा शामिल हैं। निगम अधिकारियों ने बताया कि आवंटित गुमटियों का नियमित किराया जमा करना तथा उनमें निर्धारित व्यवसाय का संचालन करना आवंटितों की जिम्मेदारी है। निगम द्वारा पूर्व में नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था, लेकिन कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने के बाद नियमानुसार यह कार्रवाई की गई। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निगम की संपत्तियों के उपयोग एवं किराया भुगतान से संबंधित नियमों का पालन अनिवार्य है।

मायादेवी बिजौरा का निधन, समाज प्रमुखों ने दी श्रद्धांजलि

अमलेश्वर। ग्राम दैमार निवासी माया देवी बिजौरा का 22 अगस्त दिन शनिवार को आकस्मिक निधन हो गया है जिसका अंतिम कार्यक्रम गृह ग्राम दैमार किया गया। माया देवी बिजौरा छत्तीसगढ़ मन्वा कुर्मी क्षेत्रिय समाज के पूर्व केंद्रीय युवा अध्यक्ष ललित कुमार बिजौरा की चानी एवं बिंदू बिजौरा, ममता, कुसुमलता , मनीषा की माता थी उनका उम्र 69 वर्ष था। दशग्रात्र कार्यक्रम 31 अगस्त दिन सोमवार को गृह ग्राम दैमार में सम्पन्न होगा। उनके निधन पर समाज के अजय सिंगौर, विजय सिंगौर, बरिन्द्र बंखोर, प्रभाकर वर्मा, प्रभात वर्मा, सुनील वर्मा, अश्वनी वर्मा, नरेंद्र वर्मा, लक्ष्मीराम बिजौरा, शशीन, प्रमोद, विनोद, प्रकाश, प्रदीप, गोलु, मनीष, अभिषेक सहित गांव के लोगों ने दुःख व्यक्त करते हुए विनम्र शोक संवेदना प्रगट किया है।

मुख्य डालकर मरम्मत कार्य कराया जा रहा, पहले भी इस तरह की खामियां आ चुकी सामने

दिग्विजय स्टेडियम के मेंटनेंस की खुली कलाई, मैदान की मिट्टी धसकी, मॉनिटरिंग पर भी सवाल

प्रशासनिक अधिकारियों की सख्ती जरूरी, मनमानी पर तभी कसेगी नकेल, खिलाड़ियों को होगा नुकसान

राजनांदगांव। दिग्विजय स्टेडियम अपने बनने से लेकर अब तक सुर्खियों में रहा है। पहले निर्माण में गड़बड़ी, तो कभी क्रिकेट संघ का कब्जा। अब बारी है उसके मेंटनेंस के सवाल पर। मैदान में देखा जा सकता है कि मिट्टी धसक रही है, जिस पर मुख्य डालकर मरम्मत की जा रही है। करोड़ों रूपए की लागत और मेंटनेंस पर बड़े खर्च के बावजूद ग्राउंड की यह दुर्दशा समझ से परे है। दिग्विजय स्टेडियम समिति की कार्यप्रणाली को लेकर ही सवाल उठने लगा है। स्टेडियम समिति के कामकाज का ब्यौरा



किसी के पास नहीं है, वह किस तरह से काम कर रही है। केवल साल में क्रिकेट का आयोजन और खिलाड़ियों के अभ्यास को ही उपलब्धियों में गिना दिया जाता है। इसके विपरित अब ग्राउंड का मेंटनेंस भी ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है। यहीं कारण है कि मैदान की मिट्टी धसकने लगी है। जानकारों की मानें तो समय-समय पर मेंटनेंस नहीं होने के कारण ही यह दशा देखने को मिल रही है।

किस मॉनटरिंग, यह भी पता नहीं

करोड़ों रूपए खर्च कर दिग्विजय स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया गया। इसके बाद उसके मेंटनेंस की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, इसका पता नहीं है। समिति तो बना दी गई, उसमें नए सदस्यों और पदाधिकारियों को भी जोड़ दिया गया। लेकिन अंदरखाने क्या चल रहा है, वह बाहर नहीं आ पा रहा है। लेकिन निर्माण के बाद मेंटनेंस में लापरवाही का नतीजा जरूर इस तरह सामने आ रहा है।

पहले भी ऐसा हो चुका, फिर भी लापरवाही सामने आई

पूर्व में भी दिग्विजय स्टेडियम मैदान पर मिट्टी धसकने और उसकी क्वालिटी को लेकर सवाल उठ चुके हैं। उस पर भी इसी तरह मरम्मत करकर खानापूर्ति कर दी गई। लेकिन उस पर ठोस कदम नहीं उठाए गए। यहीं कारण है कि दोबारा मैदान की देखरेख को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब देखा होगा कि इस पर प्रशासनिक अधिकारी कितनी रूचि दिखाएंगे।

पहले भी ऐसा हो चुका, फिर भी लापरवाही सामने आई

पूर्व में भी दिग्विजय स्टेडियम मैदान पर मिट्टी धसकने और उसकी क्वालिटी को लेकर सवाल उठ चुके हैं। उस पर भी इसी तरह मरम्मत करकर खानापूर्ति कर दी गई। लेकिन उस पर ठोस कदम नहीं उठाए गए। यहीं कारण है कि दोबारा मैदान की देखरेख को लेकर सवाल

अभियान चलाकर पशुपालकों पर कार्रवाई होना चाहिए

इस पूरे मामले को देखा जाए तो प्रशासनिक अमले की लापरवाही को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसी दूसरी कड़ी गोवंशों के मालिक है, जो उन्हें आवारा ही छोड़ देते हैं। उनके कारण ही ये हादसे हो रहे हैं, इसमें गोवंशों की जान तो जा ही रही है, साथ ही वाहनों से बड़े हादसों का खतरा भी बना हुआ है। इसलिए मालिकों पर सीधे कार्रवाई की जानी चाहिए।

नगर निगम, पुलिस और प्रशासनिक अमला, फिर भी हाल ऐसा

गोवंशों को पकड़ने, रोड से हटाने और कार्रवाई करने के लिए तीन टीमों हैं। इनमें पहले नंबर पर नगर निगम, दूसरे में पुलिस का यातायात विभाग और फिर प्रशासनिक टीम। तीन टीमों के पास जिम्मेदारी होने के बाद भी सड़कों पर गोवंशों को आसानी से देखा जा सकता है, वह भी सड़क के बीचोंबीच। जिसके चलते हादसे हो रहे हैं। मालिकों पर कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही ड्यूटी कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

हर खेत का हो डिजिटल सर्वे, हर किसान का हो पंजीयन: कलेक्टर एग्रीस्टेक और बकेट क्लेम पंजीयन को प्राथमिकता देने कलेक्टर सिंह ने दिए निर्देश

दुर्ग। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण योजना एवं अन्य कृषि सांख्यिकी योजनाओं के संबंध में वार्षिक प्रशिक्षण आज पीडब्ल्यूडी सभागार में सभी अनुविभागीय अधिकारी, उप संचालक कृषि, तहसीलदार एवं पटवारी के लिए आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अग्र कलेक्टर हरवर्ष सिंह मिरी भी उपस्थित थे। सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा अधिकारियों को योजनाओं की प्रक्रिया एवं कार्यों की बारीकियों को विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर अभिजीत सिंह ने फसलों के डिजिटल फसल सर्वेक्षण, एग्रीस्टेक पोर्टल एवं लॉन्च बकेट क्लेम प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्य आगामी सितंबर माह तक पूर्ण करने को कहा। उन्होंने सर्वेक्षण में आ रही दिक्कतों की जानकारी लेते हुए सर्वेक्षकों पर गोवंशों को आसानी से देखा जा सकता है, वह भी सड़क के बीचोंबीच। जिसके चलते हादसे हो रहे हैं। मालिकों पर कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही ड्यूटी कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।



अनुमोदन करने को कहा। कलेक्टर सिंह ने कहा कि कई गांवों में सर्वेक्षण पूरा होने के बावजूद पटवारियों द्वारा समय पर अनुमोदन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि पटवारी सर्वेक्षकों के साथ कम से कम एक-दो खसरा का मौके पर निरीक्षण करें। किसी खेत में फसल को लेकर संदेह होने पर सर्वेक्षक संबंधित फसल का फोटो संबंधित अधिकारी व पटवारी के साथ साझा करें, ताकि किसी संदिग्ध या प्रतिबंधित फसल की जानकारी मिलने पर नियमानुसार रिपोर्ट की जा सके। उन्होंने सक्रिय सर्वेक्षकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि निष्क्रिय

सर्वेक्षकों को हटाकर उनके स्थान पर दूसरे सर्वेक्षकों की नियुक्ति की जा सके। कलेक्टर ने जानकारी दी कि डिजिटल फसल सर्वेक्षण केवल धान की फसल तक सीमित नहीं है। धान के स्थान पर कोदो, कुटकी, अरहर, कपास, सोयाबीन, तिल, आदि सहित अन्य फसलों लेने वाले किसानों की फसलों का भी सर्वेक्षण किया जाना है, ताकि पात्र किसानों को नियमानुसार अनुदान का लाभ मिल सके। कलेक्टर सिंह ने एग्रीस्टेक पोर्टल पर किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने तथा लॉन्च बकेट क्लेम प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

राजस्व प्रकरणों में लापरवाही पर संभाग आयुक्त ने तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित



दुर्ग। प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही और जनसमस्याओं के निराकरण में विफलता के गंभीरता से लेते हुए संभागायुक्त दुर्ग सत्य नारायण राउटर ने राजनांदगांव जिले के भुमका तहसील में पदस्थ तहसीलदार मुकेश कुमार ठाकुर की तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत की गई है। उल्लेखनीय है कि तहसीलदार मुकेश कुमार ठाकुर पर शासकीय

कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बताने, सामान्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण में देरी करने तथा आर.बी.सी. 6-4 के तहत पीडित परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता के मामलों में अनावश्यक विफल करने के गंभीर आरोप थे। संभागायुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत निलंबन अवधि में ठाकुर का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, राजनांदगांव निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते को पात्रता होगी।

आयुक्त ने नेहरू नगर एसएलआरएम सेंटर का किया निरीक्षण, सीएंडडी वेस्ट प्लांट का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुरेश सिंह ने नेहरू नगर स्थित एसएलआरएम सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परिसर में निर्माणाधीन सीएंडडी (कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन) वेस्ट प्लांट के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी को कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने निर्माणाधीन प्लांट का निरीक्षण करते हुए कार्य की प्रगति की जानकारी ली तथा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए तथा कार्य को समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही आयुक्त ने एसएलआरएम सेंटर में संचालित कचरा संग्रहण (गीला-सूखा एवं अन्य श्रेणियों में अपशिष्ट पृथक्करण)



कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर कार्यप्रणाली का अवलोकन करते हुए संग्रहण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने एसएलआरएम सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति व्यवस्था को हाईटेक करने के निर्देश भी दिए, ताकि कर्मचारियों की उपस्थिति की नियमित एवं पारदर्शी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्था में

बोरसी भाठ में 'वन महोत्सव' का आयोजन, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव होंगे मुख्य अतिथि

दुर्ग। पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'लाइफ (लाइफ स्टैंडल फॉर एनवायरमेंट)' अभियान के तहत दुर्ग वनमंडल ग्राम 25 अगस्त 2026 (मंगलवार) को 'वन महोत्सव' का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम दुर्ग के बोरसी भाठ में पूर्वाह्न 10.00 बजे से आयोजित होगा। आयोजन में स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि विधायी कार्य विभाग मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल करेंगे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में दुर्ग ग्रामीण विधायक एवं राज्य ग्रामीण व अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित चंद्रकर उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अहिल्या विधायक व राज्य अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष योगेश लाल कोरसैवाड़ा, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेना। पूर्व मुख्यमंत्री व पाटन विधायक भूपेश बघेल, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे।

नगर पालिका परिषद अमलेश्वर अंतर्गत 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण हेतु 1.050 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 4-1 की कड़िका 2.6 में निहित प्रावधानों के तहत नगर पालिका परिषद अमलेश्वर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण हेतु शासकीय भूमि के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है।

जारी आदेश के अनुसार, तहसील पाटन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीन विभिन्न ग्रामों में स्थित कुल 1.050 हेक्टेयर शासकीय भूमि एक रूपरेखा प्रति वर्गफीट की दर से निर्धारित मूल्य राज्य कोष में जमा कराए जाने के उपरांत बिना भू-भाटक के नगर पालिका परिषद अमलेश्वर को हस्तांतरित की गई है। आवंटित भूमि के विवरण के अनुसार, ग्राम अमलेश्वर (पटवारी हल्का नंबर 03) स्थित खसरा नंबर 671/2 का 0.050 हेक्टेयर (5,380 वर्गफीट) भाग निर्धारित मूल्य 5,380 रूपए, ग्राम भोथली (पटवारी हल्का नंबर 03) स्थित खसरा नंबर 137/1 का 0.800 हेक्टेयर (86,111 वर्गफीट) भाग निर्धारित मूल्य 86,111 रूपए, तथा ग्राम खुदमुड़ा (पटवारी हल्का नंबर 03) स्थित खसरा नंबर 530 का 0.200 हेक्टेयर (21,520 वर्गफीट) भाग निर्धारित मूल्य 21,520 रूपए जमा कराए जाने पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृत किया गया है। उक्त भूमि का आवंटन कड़े प्रशासनिक प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन किया गया है। जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि आवंटित भूमि का उपयोग केवल सार्वजनिक जनउपयोगी कार्य एवं निर्धारित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु ही किया जाएगा, और अन्य किसी प्रयोजन में उपयोग किए जाने अथवा शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा।